

वर्तमान भारतीय परिदृश्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति— 2020 की उपादेयता

¹डॉ० कृष्ण कुमार सिंह

¹एसोसिएट प्रोफेसर बी.एड. विभाग, रामनगर पीजी कॉलेज, रामनगर, बाराबंकी (उ०प्र०)

Received: 20 Nov 2020, Accepted: 30 Nov 2020, Published with Peer Review on line: 31 Jan 2021

Abstract

नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा जनवरी 2015 में कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम के नेतृत्व में समिति द्वारा शुरू की गई थी और 2017 में समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 2017 की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मसौदा 2019 में पूर्व प्रमुख कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में नई टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

मुख्य शब्द— वर्तमान भारतीय परिदृश्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति— 2020, भविष्य, संभावनाएं, उपादेयता।

Introduction

“शिक्षा करेगी नवयुग का निर्माण,

आने वाला समय देगा इसका प्रमाण”

पूरे 34 वर्षों के अंतराल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव लाया गया है और बदलाव लाना भी जरूरी था। गांधीजी के अनुसार, “शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आजीविका उपार्जन के योग्य बनाना है, जिससे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। गांधीजी के इस विचार को भारत सरकार अब नई शिक्षा नीति— 2020 के माध्यम से साकार करने जा रही है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी के तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का तात्पर्य था कि “मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। सबसे पहले “शिक्षा” क्या है, इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है, सीखने और सिखाने की क्रिया, परंतु इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, इसका कोई उद्देश्य शक्तियों का विकास और व्यवहार को परिष्कृत करना है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति— 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर “शिक्षा मंत्रालय” कर दिया गया है। भारतीय परिदृश्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा देश

में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ-साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य एक बच्चे को कुशल बनाने के साथ-साथ, जिस भी क्षेत्र में रुचि रखता है, उसी क्षेत्र में, उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस तरह सीखने वाले अपने उद्देश्य और अपनी क्षमताओं का पता लगाने में सक्षम होते हैं। शिक्षार्थियों को एकीकृत किया जाना चाहिए, यानी उन्हें प्रत्येक अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी यही बात लागू होती है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के सुधार पर जोर दिया गया है।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि,

“विद्यार्थी करें अपने सपने साकार

नई शिक्षा नीति का यही आधार”।

नई शिक्षा नीति एक नए पाठ्यक्रम और शिक्षा की संरचना के गठन की कल्पना करती है, जो छात्रों को सीखने के विभिन्न चरणों में मदद करेगी। शिक्षा को शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तक पहुंचाने के लिए मौजूद शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया जाना चाहिए। यह लक्ष्य 4- गुणवत्ता शिक्षा को पूरा करके स्थिरता को पूरा करने की ओर अग्रसर होगा।

नई शिक्षा नीति शिक्षार्थियों के लिए एकीकृत विकास पर केंद्रित है। यह 10+12 सिस्टम को 5+3+3+4 के साथ बदल देता है। जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री स्कूलिंग शिक्षा होती है, इस प्रकार बच्चों को पहले चरण में स्कूल शिक्षा का अनुभव होता है।

परीक्षाएं केवल 3, 5 और 8वीं कक्षा में आयोजित की जाएंगी, अन्य कक्षाओं का परिणाम नियमित मूल्यांकन के तौर पर लिए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा को भी आसान बनाया जाएगा और एक वर्ष में दो बार आयोजित किया जाएगा ताकि प्रत्येक बच्चों को दो मौका मिले। नीति में पाठ्यक्रम से बाहर निकालने के लिए अधिक लचीलापन के साथ स्नातक कार्यक्रमों के लिए एक बहु-अनुशासनात्मक और एकीकृत दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है।

राज्य और केंद्र सरकार दोनों शिक्षा के लिए जनता द्वारा अधिक से अधिक सार्वजनिक निवेश की दिशा में एक साथ काम करने और जल्द जीडीपी को 6% तक बढ़ाएंगे। नई शिक्षा नीति सीखने के लिए पुस्तक का बोझ बढ़ाने के बजाय व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ाने पर ज्यादा केंद्रित है। एनईपी यानी नई शिक्षा नीति सामान्य समूह चर्चा और तर्क द्वारा बच्चों के विकास और उनके

सीखने की अनुमति देता है। एनटीए राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों के लिए काम प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा।

छात्रों को पाठ्यक्रम के विषयों के साथ-साथ, सीखने की इच्छा रखने वाले पाठ्यक्रम का चयन करने की स्वतंत्रता होगी, इस तरह से कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार एनआरएफ की स्थापना करके विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर अनुसंधान और नवाचारों के नए तरीके स्थापित करेगी। गांधीजी का मानना था कि "बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में देनी चाहिए।

भाषा का कार्यान्वयन यानी क्षेत्रीय भाषाओं में जारी रखने के लिए 5वीं कक्षा तक पढ़ाना एक बड़ी समस्या हो सकती है। बच्चों का क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा और इसलिए अंग्रेजी भाषा के प्रति दृष्टिकोण होगा, जो 5वीं कक्षा पूरा करने के बाद आवश्यक है। बच्चों को सकारात्मक तरीके से सीखने के अधीन किया गया है, जिससे उनके छोटे दिमाग पर बोझ बढ़ सकता है। यह सीखने वाले की आत्म-क्षमता संज्ञानात्मक कौशल पर जोर देता है। यह एक बच्चे को अपनी प्रतिभा विकसित करने में मदद करेगा। यदि वे जन्मजात प्रतिभावान हैं तो।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच नवीन विचारों के समावेश के साथ सहभागिता, महत्वपूर्ण सोच और तर्क करने की क्षमता को विकसित करना है। नई शिक्षा नीति कई उपक्रमों के साथ रखी गई है, जो वास्तव में वर्तमान परिदृश्य की जरूरत है। नीति का संबंध अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ कौशल विकास पर ध्यान देना है। किसी भी चीज के सपने देखने से वह काम नहीं करेगा क्योंकि उचित योजना और उसके अनुसार काम करने के लिए केवल उद्देश्य पूरा करने में मदद मिलेगी, जितनी जल्दी एनईपी के उद्देश्य प्राप्त होंगे, उतना ही जल्दी हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर करेगा।

राकेश सिन्हा कहते हैं कि "यह पहली बार है कि शिक्षा नीति को व्यापक परामर्श से तैयार कर बनाया गया है। इस शिक्षा नीति की दूसरी विशेषता यह है कि, यह नीति क्लास रूम से बाहर शिक्षा को ले जाने की पहल है। नई शिक्षा नीति ने उसे रोजगार से जोड़ा है, वोकेशनल एजुकेशन को इस लिहाज से जोड़ा गया है कि अब तक शिक्षा का मतलब फार्मल एजुकेशन से हुआ करता था लेकिन अब अनौपचारिक यानी इन-फॉर्मल एजुकेशन को भी शिक्षा के दायरे में लाया गया है। कोविड के दौर में जो आर्थिक संकट नजर आ रहा था उसकी एक वजह लोगों में स्वरोजगार की भावना और उसके प्रति सम्मान की कमी। नई शिक्षा नीति इसी को दूर करेगी। अर्थात् भविष्य में

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। जिससे भविष्य में अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है।

निष्कर्ष:— नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक अच्छी नीति है, क्योंकि इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को समग्र लचीला बहु-विषयक बनाना है जिसमें नीति का आशय कई मायनों में आदर्श प्रतीत होता है लेकिन यह वह कार्यान्वयन है, जहां सफलता की कुंजी निहित है। नई शिक्षा नीति कई उपक्रमों साथ रखी गई है जो वास्तव में वर्तमान परिदृश्य की जरूरत है। नीति का संबंध अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ कौशल विकास पर ध्यान देना है। किसी भी चीज के सपने देखने से काम नहीं करेगा, क्योंकि उचित योजना और उसके अनुसार काम करने से केवल उद्देश्य पूरा करने में मदद मिलेगी, जितनी जल्दी एनईपी के उद्देश्य प्राप्त होंगे, उतने ही जल्दी हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर करेगा।

संदर्भ:—

1. त्यागी गुरुसरन दास: भारत में शिक्षा का विकास, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा—2
2. गुप्ता एस.पी: भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास: शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज
3. Draft National Education Policy 2019] [http@ innovate\]](http://innovate.gov.in/innovation/2015/2016/mygov159610111.pdf)
Mygov-in@upcondent@upload@2015@2016@mygov159610111-pdf
- 4- Draft National Education Policy 2020]
[http@www-mhrd-gov-in@sites@uploadfiles@mhrd@files@nep@NEP Final](http://www-mhrd-gov-in/sites/uploadfiles/mhrd/files/nep@NEP Final English-pdf)
English-pdf
Referred on 10@08@2020
- 5- Kumar] K(2005), Quality of Education at the beginning of the 21th Century] lesson for India] Indian Educational review 40¼1½
- 6- शिक्षा एवं विद्या (1998): अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा- 281003
- 7- AED Journal of Educational Studies% Volume 4 Number 1] Feb 2015
1976] i`0 255